and from 65 in 1950-51 to 40 in 1969-70 and further to 37 in 1970-71 on the metre gauge. Similarly, the number of wagons (in terms of four-wheelers of standard carrying capacity), used to move a million net tonne kilometres per day has decreased on the broad gauge from 1,402 in 1950-51 to 1,087 in 1969-70. This figure for 1970-71 stands at 1,106. The slight increase in 1970-71 should be viewed in the light of the decline in freight traffic demands in 1970-71 and the various factors affecting operation, such as the law and order situation, particularly in the Eastern Region, thefts of communication cables and overhead equipment, wagon fittiings, etc., which have had their inevitable repurcussions on freight traffic movemant. On the metre gauge, the number of wagons of standard capacity used to move a million net tonne kilometres per day has been brought down from 2,771 in 1950-51 to 1,994 in 1969-70 and further to 1,983 in 1970-71. The capital-at-charge, equated to 1950-51 price levels, per billion traffic units (net tonne kilometres plus passenger kilometres) has come down from Rs. 15.92 crores in 1950-51 to Rs. 13.49 crores in 1969-70. The reduction in the number of locomotives and wagons per unit of traffic broadly indicates the extend of saving in capital investment and consequently in the recurring expendiure on repairs and maintenance, provision for depreciation and interest charges, which would otherwise have been incurred.

Productivity of staff, measured by the number of traffic units (net tonne kilometres plus passenger kilometres) moved per employee on the open line has increased from 122 thousands per annum in 1950-51 to 185 thousands in 1969-70 and further to 187 thousands in 1970-71.

The overall operating-cum-efficiency index de ived from sixteen selected items generally accepted as indices of efficiency of railway working and covering the salient aspects of operation, has gone up from 100 in 1950-51 to 120.9 in 1969-70 and to 121.4 in 1970-71.

मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए प्रयुक्त नदियों का पानी

7527. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियों के जलका, उस प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में जिनसे हो कर नदियां बहती हैं; कितना-कितना प्रतिशत सिंचाई के काम में लाया जाता है ; और

(ख) मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) मध्य प्रदेश में मुख्य नदी बेसिन, नर्मदा, ताप्ती, चम्बल, बेतवा, केन, सोन, महानदी और गोदावरी है। इन नदियों के अपने मुहानों पर कुल जलसाधनों का और 1968-69 तक मंजूरी दी गई परियोजनाओं के पूर्ण होने पर उनके उपयोग का एक मोटा अन्दाजा नीचे दिया जाता है :—

नदी प्रणाली	जल साधन (दस लाख फुट)	1968-69 तक मंजूरी दी गई परियोजनाओं के पूर्णतः विकसित हो जाने पर उनका उपयोग	
		मध्य प्रदेश	बेसिन में अन्य राज्य
नर्मदा	28	2.7	2.4
ताप्ती	10	नगण्य	4
चम्बल	10	2	3
बेतवा और केन	10	0.6	2
सोन	12	नगण्य	5
महानदी	50	3.0	8
गोदावरी	90	नगण्य	15

(ख) मध्य प्रदेश सरकार सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं के विकास को अधिकाधिक महत्व दे रही है। योजनाओं के दौरान, 25 लाख एकड़ की कुल शक्यता वाली 7 बड़ी और 50 मध्यम स्कीम आरम्भ की गई हैं। इनसे 10.7 लाख एकड़ की शक्यता पहले ही बढ़ चुकी है और मार्च 1974 तक इसके बढ़ कर 19.5 लाख एकड़ तक पहुंच जाने की आशा है। विभिन्न योजनाओं में किया गया परिव्यय इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

प्रथम योजना	30
दूसरी योजना	37
तीसरी योजना	20
1966-69	
चौथी योजना (लक्ष्य)	83

मध्य प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि में सिंचित भूमि का अनुपात

7528. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि में सिंचित भूमि का अनुपात कितना है ;

(ख) मध्य प्रदेश के समीपवर्ती राज्यों में कुल कृषि योग्य भूमि में सिंचित भूमि का अनुपात कितना है ;

(ग) इस अनुपात को इस सम्बन्ध में समीपवर्ती राज्यों के समान लाने के लिए मध्य प्रदेश को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ; और

(घ) गत तीन योजनाओं के दौरान प्रत्येक योजना में मध्य प्रदेश को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख). कुल फसली क्षेत्र और वृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से सिंचाई-शक्यता, और मध्य-प्रदेश और उससे सटे राज्यों में कुल फसली क्षेत्रफल की तुलना में उसकी प्रतिशतता दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ). सिंचाई राज्यों का मामला है और सिंचाई-परियोजनाओं के लिए राज्य सरकारें धन की व्यवस्था अपने कुल योजना परिव्यय की सीमा के अन्दर ही करती हैं। मध्य प्रदेश का कुल योजना परिव्यय, उसके लिए केन्द्रीय सहायता और वृहत् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं पर परिव्यय नीचे निर्दिष्ट है :—

अवधि	मध्य प्रदेश का कुल योजना परिव्यय	योजना के लिए मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सहायता	वृहत् और मध्यम सिंचाई क्षेत्र में परिव्यय
प्रथम योजना	94	61	8 (लगभग)
दूसरी योजना	145	96	30
तीसरी योजना	288	219	37
1966-69	173	142	20
चौथी योजना (लक्ष्य)	393	262	96